भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 2925
गुरुवार, 08 अगस्त, 2024/17 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

धनबाद में नए विमानपत्तन की स्थापना

2925. श्री दुलू महतोः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का धनबाद संसदीय क्षेत्र में एक नया विमानपत्तन स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा धनबाद में उक्त विमानपत्तन कब तक स्थापित होने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) धनबाद में उक्त विमानपत्तन की स्थापना में क्या कठिनाइयां आ रही हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): भारत सरकार ने देश में नए ग्रीनफ़ील्ड हवाईअड्डों के विकास के लिए ग्रीनफ़ील्ड विमानपत्तन (जीएफ़ए) नीति, 2008 तैयार की है। इस नीति के अनुसार, यदि राज्य सरकार सहित कोई हवाईअड्डा विकासकर्ता किसी हवाईअड्डे को विकसित करना चाहता है, तो उन्हें उपयुक्त साइट चिह्नित करने और हवाईअड्डे के निर्माण के लिए पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन करवाने, तथा 'साइट क्लियरेंस' और तत्पश्चात 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के लिए केंद्रीय सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। भारत सरकार को ग्रीनफ़ील्ड विमानपत्तन नीति के तहत धनबाद, झारखंड में ग्रीनफ़ील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए 'साइट क्लियरेंस' हेतु न झारखंड राज्य सरकार से और न ही किसी हवाईअड्डा विकासकर्ता से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

इसके अतिरिक्त, नागर विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने और जनसाधारण के लिए हवाई यात्रा को किफ़ायती बनाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) शुरू की है, जो मांग आधारित योजना है। मौजूदा धनबाद हवाईअड्डा, जो झारखंड राज्य सरकार का है, उड़ान योजना दस्तावेज़ में असेवित हवाईअड्डों की सूची में शामिल है।

झारखंड में धनबाद हवाईअड्डे के लिए उड़ान 5.2 के तहत छोटे विमान (20 सीटों से कम) के लिए बोली प्राप्त हुई है। छोटे विमान (2बी) के प्रचालन और आने वाले समय में 3सी श्रेणी के विमानों के प्रचालन के लिए हवाईअड्डे के विस्तार हेतु भूमि की उपलब्धता के संबंध में झारखंड राज्य सरकार से सहमति और समर्थन प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। तथापि, भूमि प्रतिबंधों के कारण झारखंड राज्य सरकार ने धनबाद हवाईअड्डे के विकास के लिए सहमति नहीं दी है।

*****